फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 76 संख्याः 280 प्रभात जयपुर, गुरूवार 14 मई, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

Don't Stake Money And You Win!

Somewhere between the sixes and the wickets, an advertisement pops up, a celebrity grinning, telling you that depositing a hundred rupees on some gaming app could make you rich by morning...

The Game on the Temple Steps

यूपी की भांति बंगाल में भी ''बुलडोज़र'' का खुलकर उपयोग होने लगा है

उपयोग की शुरुआत तितजला क्षेत्र में कल आगजनी की घटना से हुई

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मई। उत्तर प्रदेश की तरह ही, पश्चिम बंगाल में हाल ही में चुनी गई भाजपा सरकार बुलडोज़र के साथ अत्यधिक सक्रिय हो गई है। नए मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के सीधे आदेश पर, राज्य प्रशासन ने कलकत्ता के टिलजला इलाके में एक अवैध मकान और फैक्ट्री की इमारतों को गिराने के लिए तीन बुलडोज़र लगा दिये।

इस कार्रवाई की वजह टिलजला इलाके में कल लगी भीषण आग थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हुए। इसके अलावा, लगभग 27 अन्य लोग भी घायल हुए। नए शहरी मामलों की मंत्री, अग्निमित्रा पॉल ने घायल लोगों से अस्पताल में मुलाकात की।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- एक मकान में आग लगने से दो व्यक्तियों की मौत तथा तीन गंभीर रूप से घायल हुए थे। नगरीय विकास मंत्री, अग्निमित्रा पॉल मरीजों को देखने अस्पताल पहुँची तथा हॉस्पिटल की हालत देखकर मंत्री महोदय ने तत्काल अस्पताल में गंदगी हटाने के आदेश दिए। नई सरकार कोई मौका नहीं गंवाना चाहती, जिससे उसे शहरों में मीडिया का पूर्ण सहयोग मिलता रहे।
- इसी प्रकार की घटना तोपसिया क्षेत्र में भी हुई। चमड़े (लैदर) को प्रोसेस करने वाली फैक्ट्रियों में कर्मचारियों को महफूज़ रखने के लिए कई ऑर्डर दिए हैं, हाई कोर्ट ने।
- कोलकाता के पूर्वी क्षेत्र में आग की दुर्घटना के बाद फैक्ट्री मालिक व मैनेजर को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन फैक्ट्रियों में कंस्ट्रक्शन की इजाज़त पूर्व नगरीय विकास मंत्री, फिराद हकीम के कार्यकाल में मिली थी।
- नई सरकार ने डिटेल रिपोर्ट माँगी है, जिससे यह आंका जा सके कि राज्य में किसने इतनी भारी संख्या में गैर कानूनी तरीके से निर्माण की इजाज़त हासिल की थी। नई सरकार द्वारा ऑडिट कराने के बाद, सेफ्टी के कायदे-कानून की अवहेलना करने वाले सभी निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए जाएंगे।

क्या सोनिया के चैकअप के कारण टला केरल पर फैसला

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मई। सोनिया गांधी के बुधवार को यहाँ स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल चले जाने के कारण कांग्रेस के अगले मुख्यमंत्री के चयन में और विलम्ब हो गया। हालांकि पार्टी सूत्रों के अनुसार, घोषणा संभवत: बुधवार रात तक की जा सकती है।

इस विलंब के कारण दो मुख्य दावेदारों, एआईसीसी महासचिव के. सी. वेणुगोपाल और विधानसभा में विपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन की असमंजस की स्थिति यथावत बनी हुई है।

- सोनिया गांधी काफी समय से अस्वस्थ हैं और बुधवार को उन्हें स्वास्थ्य जाँच के लिए अस्पताल जाना पड़ा था।

राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को बैठक कर वेणुगोपाल पर फैसला अंतिम रूप देने की कोशिश की। पार्टी के केन्द्रीय पर्यवेक्षकों, अजय माकन और मुकुल वासनिक, के अनुसार, अधिकांश पार्टी विधायक भी वेणुगोपाल के पक्ष में हैं।

यह कदम मंगलवार को राहुल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असम में समान नागरिक संहिता लागू होगी

नवनिर्वाचित मु.मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव को मंजूरी दी

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मई। गंगोत्री से गंगासागर का लक्ष्य पूरा होने के बाद, भाजपा के अब नए क्षेत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है।

अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ लेने के तुरंत बाद, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज राज्य की पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। लेकिन एक शर्त के साथ, कि जनजातीय आबादी यूसीसी के दायरे से बाहर रहेगी। देर-सवेर पश्चिम बंगाल में शुभेन्दु अधिकारी की सरकार भी इसी दिशा में कदम बढ़ा सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान, केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने 19 अप्रैल को एक चुनाव रैली में स्पष्ट रूप से कहा था कि भाजपा की सरकार बनने के छह महीनों के भीतर बंगाल में यूसीसी लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा था, ''बंगाल में यूसीसी इसलिए लागू किया जाएगा, ताकि राज्य के सभी नागरिकों पर एक समान, कानून लागू हो।''

उत्तराखंड और गुजरात में यूसीसी पहले ही लागू हो चुका है, और कई भाजपा शासित राज्यों, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में समान कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है। गोवा ऐसा सबसे पुराना राज्य है, जहां यूसीसी का एक रूप 1867 के पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू था, जो 1962 में गोवा के भारतीय संघ में विलय के बाद जारी रहा। लेकिन पूरे देश में यूसीसी लागू करने की दिशा में अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में उल्लेखित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में यूसीसी बिल 26 मई को विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिल को असम की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया गया है। सरमा ने कहा, ''हमने जनजातीय आबादी को पूरी तरह यूसीसी के दायरे से बाहर रखा है। असम के जनजातीय समुदाय द्वारा पालन किए जाने वाले सभी रीति-रिवाज, परंपराएँ और प्रथाएँ यूसीसी के दायरे में नहीं आएंगी।'' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया: ''यूसीसी में उत्तराधिकार, विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप और विवाह तथा तलाक के अनिवार्य पंजीकरण आदि शामिल होंगे।

- उन्होंने स्पष्ट किया कि असम के आदिवासियों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
- चर्चा है कि इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की कवायद शुरु होगी, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी, भाजपा की सरकार बनने के 6 माह बाद राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी।
- उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम तीसरा राज्य होगा, जहाँ समान नागरिक संहिता लागू होगी।

आखिर कौन है शुभम खैरनार, जिसने नीट पेपर लीक किया?

नासिक का शुभम बीएएमएस (सर्जरी) का छात्र है, उसने पुणे में किसी संदिग्ध से पेपर खरीदा और हरियाणा में किसी अन्य को बेच दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एन.टी.ए.) ने मंगलवार को 22 लाख से ज्यादा छात्रों के लिये हुई नीट यू.जी. 2026 परीक्षा रद्द कर दी, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामने आईं कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। खबर है कि यह घोटाला महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुआ, जहां परीक्षा की पहली डिजिटल कॉपी सामने आई।

सूत्रों के अनुसार, नासिक निवासी शुभम खैरनार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने हिरासत में लिया, आरोप है कि उसने लीक हुए पेपर को पुणे के एक संदिग्ध से खरीदा और बाद में इसे 5 लाख रुपये के प्रॉफिट मार्जिन में बेच दिया।

महाराष्ट्र के बाद, लीक हुआ पेपर कथित रुप से कई राज्यों तक फैल गया, जिनमें हरियाणा के गुड़गांव, राजस्थान के जयपुर और सीकर, जो एक बड़ा कोचिंग हब है, के साथ ही, जम्मू-कश्मीर, बिहार और केरल शामिल हैं।

- शुभम खैरनार को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, बताया जाता है कि शुभम ने दस लाख रूपए में पेपर खरीदा था और उसे हरियाणा में 15 लाख रूपए में बेच दिया था।

नासिक के इंदिरा नगर इलाके का 30 वर्षीय शुभम खैरनार, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.ए.एम.एस.) का छात्र है। कथित तौर पर उसने पुणे के एक संदिग्ध से नीट यूजी पेपर 10 लाख रुपये में खरीदा और हरियाणा के एक खरीदार को 15 लाख रुपये में बेचकर 5 लाख रुपये का मुनाफा कमाया। रिपोर्टों के अनुसार, पेपर एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन के जरिए प्रसारित किया गया।

2 मई की रात 11 बजे, राजस्थान के सीकर के एक एम.बी.बी.एस. छात्र, जो केरल में पढ़ रहा था, ने ''गैस पेपर'' अपने पिता को भेजा, जो सीकर में कोचिंग छात्रों के लिए एक हॉस्टल चलाते हैं। नीट परीक्षा 3 मई को होने वाली थी और नीट परीक्षा में केवल कुछ ही घंटे बाकी थे। पिता और पुत्र को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अनजाने में वो नीट परीक्षा पेपर लीक का हिस्सा बन गए हैं, जिसके नाटकीय नतीजे होंगे, जैसे, पूरा एग्ज़ाम कैंसल हो जाएगा और सी.बी.आई. केस को टेकओवर कर लेगी।

विशेष ऑपरेशंस ग्रुप के सूत्रों ने बताया कि केरल के छात्र को ''गैस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुलायम के छोटे पुत्र का निधन

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मई। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव का लखनऊ में 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें बुधवार को लखनऊ सिविल अस्पताल मृत अवस्था में लाया गया।

- स्व. मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव (38 वर्ष) लंबे समय से फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित थे।

वे भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले भाई थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, उन्हें सुबह 6:15 बजे उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अस्पताल लाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी पत्नी उस समय मौजूद नहीं थीं।

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम जल्द ही उनके शरीर का पोस्टमॉर्टम

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'पेड़ों को बचाने के लिए 1730 में जोधपुर महाराजा द्वारा दिये गये ''फरमान'' की आज जरूरत है'

राजस्थान हाईकोर्ट ने खेजड़ी के पेड़ बचाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की

जयपुर, 13 मई (कास.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने खेजड़ी के पेड़ों की गैरकानूनी तरीके से कटाई को रोकने और राज्य सरकार को पेड़ों को बचाने के लिये एक नया कानून और गाइडलाइन जारी करने के मुख्य उद्देश्य से दायर याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश अरुण मुगा और न्यायाधीश संदीप शाह ने सुनवाई की। याचिकाकर्त्ता 'श्री ज़म्भेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था' की ओर से हाल में बीकानेर में खेजड़ी के पेड़ काटकर सोलर प्लांट लगाये जाने के विरोध में प्रदर्शन के परिप्रेक्ष्य में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने मुख्य सचिव के माध्यम से राजस्थान सरकार, वन विभाग, पर्यावरण विभाग, कलेक्टर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ इत्यादि के साथ-साथ, ऊर्जा विभाग और राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉपोरेशन लिमिटेड (आर.आर.ई.सी.एल.) को भी पक्षकार बनाया है। उल्लेखनीय है कि आरआरआईसीएल प्रदेश में सौर ऊर्जा से संबंधित नीति बनाती है और सौर प्लांट लगाने के टेंडर भी करती है।

- इस मामले में ''श्री ज़म्भेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था'' द्वारा बीकानेर में सोलर प्लांट लगाए जाने के लिए खेजड़ी के पेड़ काटने के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के संदर्भ में याचिका दायर की गई थी।
- याचिकाकर्ता की गुहार थी कि खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए कानून लाया जाए और इस संदर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा 9 मार्च को गठित विशेष समिति, जो इसी मुद्दे पर अपना निष्कर्ष देगी, उसे सहयोग करने का अवसर भी दिया जाये।

उल्लेखनीय है कि बीकानेर में खेजड़ी के पेड़ काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन भी किये जा रहे हैं और दादूपंथी समुदाय के सदस्यों द्वारा भी आमरण अनशन किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय विश्नोई पेश हुये थे। उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि खेजड़ी के पेड़ों का कई समुदायों के साथ धार्मिक व भावनात्मक जुड़ाव है, और इन पेड़ों को काटे जाने के विरोध में विश्नोई समाज की 363 महिलाओं ने सन् 1730 में सामूहिक आत्महत्या का रास्ता अपनाया था। उल्लेखनीय है कि 1730 में तत्कालीन जोधपुर महाराजा अभय सिंह ने खेजड़ी के पेड़ काटने के लिये अपने सिपाहियों को तैनात किया था। उसके विरोध में 84 ग्रामों की महिलाओं ने पेड़ों से लिपटकर उनको बचाने की कोशिश की थी, परंतु सैनिकों ने बेरहमी से पेड़ों को काट डाला था तथा इस प्रकार उन महिलाओं की हत्या कर दी गई थी। जब यह सूचना महाराजा अभय सिंह को मिली तो उन्होंने ग्रामीणों से माफी मांगी थी और फरमान जारी किया था कि विश्नोई गांवों में पेड़ों और जानवरों को नहीं काटा जायेगा।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बाबूलाल कटारा की पुलिस रिमांड 16 मई तक बढ़ी

जयपुर, 13 मई। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1, महानगर द्वितीय ने कृषि विज्ञान प्राध्यापक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा की रिमांड अवधि 16 मई तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही, अदालत ने सह आरोपी और कटारा के भांजे विजय कुमार डामोर को 27 मई तक जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में एसीबी कोर्ट ने आरोपी संजय बडाया को 19 मई तक जेल भेज दिया है।

- एसीबी कोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले में संजय बडाया को जेल भेजा।

रिमांड अवधि पूरी होने पर एसओजी की ओर आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। एसओजी की ओर से कहा गया कि आरोपी से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप व शी की मुलाकात, दो एकदम फर्क सोच व शासन के बीच मुकाबला है?

ट्रंप की स्टाइल, नाटकीय सौदेबाजी, सार्वजनिक धमकियां, अचानक बातचीत सफल होने की घोषणा पर निर्भर करती है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 मई। डॉनल्ड ट्रम्प 13 से 15 मई के बीच शी जिनपिंग के साथ वार्ता करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंतर संभवत: अमेरिका और चीन के बीच नहीं, बल्कि नेतृत्व, निर्णय लेने की शैली और रणनीतिक समय सीमा के दो मौलिक रूपों के बीच हो सकता है।

ट्रम्प भू-राजनीति को सामरिक दृष्टि से लेन-देन के आधार पर आधारित और प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण से देखते हैं। उनकी कूटनीति शिखर वार्ता-केन्द्रित और मीडिया-केन्द्रित है, जो तत्काल दृश्यता और सबसे छोटे मीडिया लाभ पर भी काफी ध्यान देती है। वे जल्दी ही ऐसे परिणाम चाहते हैं, जो दिखाई दें। टैरिफ, नाटकीय वार्ता, सार्वजनिक धमकी, और तेज़ी से सफलता की घोषणाएँ आदि उनके तरीके हैं। सफलता राजनीतिक रूप से और तुरंत मापी जाती है।

इस शैली की अपनी ताकत है। ट्रम्प सहज रूप से एस्केलेशन (उकसाने) के मनोविज्ञान को समझते हैं और जानते हैं कि अप्रत्याशितता स्वयं वार्ता का एक जरिया बन सकती है। वे यह भी समझते हैं कि पारंपरिक विदेश नीति की नौकरशाही अक्सर स्थिर, धीमी और घरेलू राजनीतिक भावना से अलग हो जाती है।

लेकिन सामरिक नेतृत्व अस्थिरता भी पैदा करता है।

- दूसरी ओर शी की स्टाइल में निर्णय लेने की प्रक्रिया, पार्टी व संगठन के ढांचे पर टिकी होती है तथा शी का शासन गहरी सोच व एकाग्रता पर विश्वास करता है और ट्रंप तत्कालिक व्यवस्था (इम्प्रोवाइज़ेशन) में विश्वास रखते हैं।
- ट्रंप अपनी अथॉरिटी (रूतबा) व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पर कायम करते हैं, दूसरी और शी के सिस्टम में दीर्घकालीन रणनीति में विश्वास किया जाता है तथा वे धैर्य रखते हुए तत्कालिक असुविधा को स्वीकार करते हैं तथा शी व चीन का विश्वास कूटनीति में नहीं, बल्कि दीर्घकालीन रणनीति में है।

ट्रम्प के शासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक व्यक्तिगत बजाय संस्थागत होने के। औपचारिक सलाहकार संरचनाएँ कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि प्रभाव अनौपचारिक नेटवर्क, व्यक्तिगत निष्ठावानों, मीडिया की कहानियों, व्यावसायिक आंकड़ों और संपर्क के तदर्थ चैनलों की ओर स्थानांतरित हो जाता है। नीति अक्सर अनुशासित अंतर-एजेंसी प्रक्रिया के बजाय, सहज ज्ञान, बातचीत और राजनीतिक आवेग से प्रेरित होती है।

यह न केवल विरोधियों के लिए, बल्कि मित्र और अमेरिकी संस्थानों के लिए भी अस्थिरता पैदा करता है। संकेत तेजी से बदलते हैं। स्थिति अचानक कभी मुश्किल तो कभी नरम हो जाती है। अधिकारी एक हफ्ते में सशक्त होते हैं और अगले हफ्ते हाशिए पर चले जाते हैं। नीति की दिशा ट्रम्प के अपने राजनीतिक आवेग, व्यक्तिगत अटपटे रवैये और प्रतिक्रिया से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है।

शी की नेतृत्व शैली अत्यधिक केन्द्रीकृत है, लेकिन क्रियान्वयन में गहराई से संस्थागत है। निर्णय पार्टी संरचनाओं, आंतरिक समितियों, औपचारिक पदानुक्रम और अनुशासित नौकरशाही श्रृंखलाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। शी तात्कालिक फैसलों की बजाय केन्द्रीकृत तरीके से शासन करते हैं।

शी की प्रणाली में भी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, विशेष रूप से अत्यधिक केन्द्रीकरण और पीएलए नेतृत्व के भीतर बढ़ती अशांति। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत चीनी राज्य की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विजय ने विश्वासमत जीता, अन्नाद्रमुक के 27 विधायकों ने समर्थन दिया

चेन्नई, 13 मई। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्रि कड़गम (टीवीके) सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। विजय को अपना बहुमत साबित करने के लिए 117 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें सदन में 144 विधानसभा सदस्यों का समर्थन मिला। सरकार के पक्ष में एआईएडीएम के 27 सदस्यों ने भी मतदान किया।

- टीवीके सरकार को बहुमत साबित करने के लिये 118 मतों की आवश्यकता थी, पर उसे 144 मत प्राप्त हुए।

सुबह 9:30 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही शुरू की। इसके बाद टीवीके की सरकार के विश्वास मत के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)